>

Title: Need to constitute State Re-oganisation Commission.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्षेत्रीय आर्थिक विषमता के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में तमाम प्रकार की सामाजिक और आर्थिक विषमता फैली है। तमाम क्षेत्रों में असंतोष है। बहुत सारे क्षेत्रों में लोग सूखे और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भूख से भी मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे-छोटे राज्य बनाने की मांग प्रारम्भ हुई है। उसी क्रम में केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मामला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एक अलग प्रदेश बने, इस दृष्टि से बुन्देलखंड को एक नया प्रदेश बनाने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रूप में चार विभाजन उत्तर प्रदेश के करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी वक्तव्य देती हैं और माननीय प्रधानमंत्री जब वाराणसी गये थे तो उन्होंने भी इस प्रकार का वक्तव्य दिया था।

आंध्र प्रदेश के अन्दर भी तेलंगाना की मांग आ रही है। महाराष्ट्र के अन्दर विदर्भ को अलग प्रदेश बनाने की मांग काफी समय से होती रही है। इस सम्बन्ध में केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार केवल जन-समस्याओं से आम जनता का ध्यान हटाने के लिए, आम जनता और देश की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर जब प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड आदि छोटे राज्यों को बनाने के समर्थक हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की राजनैतिक बयानबाजी कर रहे हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड राज्य बनाने में आपत्ति क्या है? इसके लिए अविलम्ब राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित हो और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल इन राज्यों में अगर पुनर्गठन की आवश्यकता वहां के आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक हित के लिए है तो इन प्रदेशों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाये।

MR. SPEAKER : I now come to item No. 25. Shri Madhusudan Mistry.

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR) : Sir, I have given notice.

MR. SPEAKER : I have seen it. The rest will be taken up at the end of the day.

Now, coming to item No. 25, Shri Madhusudan Mistry.